चिकित्सा संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट कॉर्नर

प्रदेश में लू-तापघात की आशंका को देखते हुए सरकार का निर्णय

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । प्रदेश में आगामी दिनों में लू-तापघात की आशंका को देखते हुए चिकित्सा संस्थानों में हीटवेव बचाव एवं उपचार के लिए समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किए जा रहे हैं। इमरजेंसी सुविधाओं के लिए चिकित्सा संस्थानों में हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट कोर्नर स्थापित करने के साथ ही दवा एवं जांच सहित सभी माकूल इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड ने शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में हीटवेव प्रबंधन, मौसमी बीमारियों सहित अन्य विषयों पर समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्साधिकारी हीटवेव को लेकर प्रो-एक्टिव अप्रोच के साथ काम करें। रोगी और उनके परिजनों के लिए छाया, शीतल पेयजल सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

राठौड़ ने कहा कि सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा संबंधित चिकित्सालय प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में पंखे, कूलर, एसी, वाटर कूलर, जांच, दवा-ओआरएस एवं उपचार के प्रबंधन में कोई कमी नहीं रहे। उन्होंने आवश्यकता होने पर दवाओं की स्थानीय स्तर पर खरीद करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी निरंतर फील्ड में जाकर चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण करें। उन्होंने रेपिड रेस्पॉन्स सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू कर रोगियों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।

चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड ने शुक्रवार को हीटवेव प्रबंधन और मौसमी बीमारियों की तैयारियों पर चर्चा की।

- प्रमुख शासन सचिव ने दिए हीटवेव से बचाव एवं उपचार के समुचित प्रबंध करने के निर्देश
- अधिकारी रेपिड रेस्पॉन्स सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू करें : गायत्री राठौड़
- खाद्य पदार्थों व पानी की जांच तथा 2 दिन में सभी एम्बुलेंस का सत्यापन कराने के निर्देश

राठौड़ ने गर्मी के मौसम को देखते हुए शुद्ध खाद्य पदार्थों एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि को नियंत्रण को भीडभाड वाले स्थानों, छात्रावासों सहित अन्य स्थानों पर खाद्य पदार्थों एवं पानी की जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों को चिकित्सा संस्थानों पर कार्यरत एएनएम एवं सीएचओ के कार्यों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी चिकित्सा संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे फंक्शनल हों। सभी चिकित्सा संस्थान सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम एप में अपनी रिपोर्टिंग करें। उन्होंने कहा कि एप पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर चिकित्सा संस्थानों एवं उनके प्रभारियों का मूल्यांकन किया जाएगा। जिस जिले का स्कोर कम होगा, उस जिले के संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मीडिया में प्रकाशित होने वाली नकारात्मक खबरों की मॉनिटरिंग करते हुए वांछित सुधार करने पर भी बल दिया।

प्रमुख शासन सचिव ने प्रदेश में आपातकालीन रेफरल व्यवस्था के लिए संचालित की जा रही 108 एम्बुलेंस का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में सभी 108 एम्बुलेंस में साफ-सफाई, उपकरणों एवं दवाओं की उपलब्धता और क्रियाशीलता के संबंध में आगामी दो दिवस में सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

राठौड़ ने टीबी मुक्त भारत के तहत 100 दिवसीय अभियान, गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम, भवन निर्माण एवं भूमि आवंटन, ओडीके एप में सूचनाओं की भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत के तहत 100 दिवसीय अभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविरों में प्रभावी रूप से कार्य कर सघन स्क्रीनिंग कर निर्धारित लक्ष्य अर्जित किए जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्वास्थ्य कैम्प की सूचना पूर्व में ही आमजन को दी जाए ताकि आमजन इन शिविरों का पूर्ण लाभ ले सकें। उन्होंने एचपीवी अभियान को भी गति देने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक जोगाराम ने एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने इस अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत काउंसलर्स को प्रभावी रूप से अपने दायित्व पूरे करने के निर्देश दिए।

निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने कहा कि सभी चिकित्सा संस्थानों में फायर सेफ्टी ऑडिट नियमित रूप से कराई जाए। गर्मी के मौसम को देखते हुए फायर सेफ्टी मॉकड्रिल एवं 21 अप्रेल से 26 अप्रेल तक फायर सेफ्टी सप्ताह से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाए। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने, अनुपयोगी पत्रावलियों एवं वस्तुओं का नियमानुसार निस्तारण करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉ. टी. शुभमंगला, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर, निदेशक एड्स डॉ.. सुशील परमार सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे। समस्त मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य, अधीक्षक, संयुक्त निदेशक जोन, सीएमएचओ, पीएमओ, आरसीएचओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी वीसी से जुडे।

अब 20 हजार वर्गमीटर से बड़े भूखण्ड भी होंगे उप-विभाजित

रीको प्रशासन ने लागू किए उप-विभाजन के नए नियम लागू

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यिमयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रीको ने बडे औद्योगिक भूखण्डों के उप-विभाजन को सशर्त मंजूरी प्रदान कर दी है। इस निर्णय के तहत अब रीको के आवंटी अपने बड़े भूखण्ड छोटे हिस्सों में विभाजित कर विक्रय कर सकेंगे।

रीको प्रशासन ने रीको डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स, 1979 के नियम 17 (ई) को पुन: लागू करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डों का उप-विभाजन किया जा सकेगा। उप-विभाजन के बाद प्रत्येक उप-विभाजित भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर रहेगा।

निर्धारित शर्तों के अनुसार, भूखण्ड का उप-विभाजन भूमि आवंटन के 7 वर्ष बाद ही किया जा सकेगा और संबंधित भूखण्ड विवाद रहित होना चाहिए। उप-विभाजन की प्रक्रिया के तहत आवेदक को प्रस्तावित लेआउट प्लान रीको में जमा कराना होगा, जिसे लैंड प्लान कमेटी से अनुमोदित कराया जाएगा। यदि भूखण्ड पर किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का ऋण है, तो उसकी एनओसी भी आवश्यक होगी।

- इस निर्णय से बड़े भूखण्डों का बेहतर उपयोग होगा
- निवेशकों को उद्योग लगाने के अधिक अवसर मिलेंगे

रीको ने स्पष्ट किया है कि उप-विभाजन के बाद विकसित होने वाले क्षेत्र में सड़क, ड्रेनेज, बिजली, स्ट्रीट लाइट, वर्षा जल संचयन और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं मूल आवंटी को अपने खर्च पर उपलब्ध करानी होंगी। इन सुविधाओं को तीन वर्षों के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

नियमों के अनुसार, 1500 वर्गमीटर तक के भूखण्ड के लिए न्यूनतम 18 मीटर तथा इससे बडे भूखण्ड के लिए 24 मीटर चौड़ी आंतरिक सड़क का प्रावधान रखा गया है।

वित्तीय प्रावधानों के तहत उप-विभाजन शुल्क संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित दर का 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ट्रांसफर चार्ज एवं एक स्वीकृत गतिविधि से अन्य स्वीकृत गतिविधि के परिवर्तन हेतु स्वीकृति शुल्क भी नियमानुसार देय होंगे। उप-विभाजित भूखण्ड की लीज अवधि मूल लीज अवधि से अधिक नहीं होगी और नए खरीदार को पंजीकृत दस्तावेज की तिथि से दो वर्षों के भीतर भूखण्ड का उपयोग करना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि उद्यमियों द्वारा लंबे समय से बडे भूखण्डों के उप-विभाजन की मांग की जा रही थी। ऐसे में यह निर्णय न केवल भूमि के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करेगा, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को गति देगा तथा नए निवेश एवं रोजगार के अवसर भी सृजित करेगा।

चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक गूंजा नारी शक्ति का जयघोष

जयपुर में शुक्रवार को 'नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन' का आयोजन किया गया।

जयपुर। महिला सशक्तिकरण और 'विकसित भारत' के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को जयपुर में 'नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन' का आयोजन किया गया। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में 'माय भारत' द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शहर की सैकड़ों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

सुबह 7:30 बजे चांदपोल से शुरू हुई यह रन बडी चौपड तक आयोजित की गई। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी इस दौड़ में छात्राओं, उद्यिमयों, पत्रकारों, खिलाड़ियों सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुडी महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे मार्ग पर जोश और ऊर्जा का माहौल देखने को मिला।

कार्यक्रम की थीम 'नारी शक्ति वंदन' रखी गई। रन को राज्य मंत्री मंजू बाघमार और पूर्व विधायक अलका गुर्जर ने फ्लैग-ऑफ किया। इस मौके पर पूर्व महापौर कुसुम यादव सहित कई प्रमुख महिलाएं उपस्थित रहीं। विशेष आकर्षण के रूप में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की कांस्य पदक विजेता पूजा और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 की स्वर्ण पदक विजेता कचनार चौधरी ने भी भाग लेकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया।

17 देशों के 43 प्रतिभागी रूबरू होंगे राजस्थान विधानसभा से : देवनानी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि शनिवार को विश्व के विभिन्न देशों के प्रतिभागी राजस्थान विधानसभा का अवलोकन करेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में बांग्लादेश, भूटान, घाना, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया, जाम्बिया सहित 17 देशों के 43 प्रतिभागी भाग लेंगे। स्पीकर देवनानी ने बताया कि लोकसभा सचिवालय के पार्लियामेंट्री रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसिस द्वारा इन्टरनेशनल लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग विषय पर विधायी मसौदा तैयार करने के लिए 37 वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान विधान सभा में किया जा रहा है।

यह कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग योजना के अंतर्गत संचालित हो रहा है।

देवनानी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशी प्रतिभागियों के लाभ के लिए विधायी मसौदा तैयार करने के वैचारिक जान, कौशल और तकनीकी को बढाना है।

स्पीकर देवनानी ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 18 अप्रैल को विदेशी प्रतिनिधियों का दल राजस्थान विधानसभा के सदन, भवन और राजनैतिक आख्यान संग्रहालय का भ्रमण करेगा। इससे राज्य विधानमण्डल कि पहचान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकेगी।

उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों को राज्य विधानमंडल की कार्यप्रणाली विधायी प्रक्रिया एवं संसदीय परंपराओं की जानकारी दी जाएगी। देवनानी ने बताया कि प्रतिभागियों की पीठासीन अधिकारियों और विधानसभा सचिव के साथ संवाद, प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञों एवं गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात तथा राज्य के प्रमुख विधि संस्थानों का भ्रमण भी कराया जाएगा। स्पीकर देवनानी ने बताया कि विदेशी प्रतिभागियों को राजस्थान की समृद्ध संस्कृति से परिचित कराने हेतु स्थानीय दर्शनीय स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा।

पत्नी से परेशान युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की

मरने से पहले युवक ने अपनी बहन को सुसाइड नोट भेजा था

जयपुर (कासं)। मुहाना इलाके में गत 21 फरवरी की रात एक युवक ने अपनी पत्नी से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में अब नया मोड सामने आया है। पुलिस ने मृतक की बहन के मोबाइल पर आए मैसेज के आधार पर हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में पीड़ित पिता सांगानेर के वैष्णव नगर निवासी रामनिवास बाथम ने अपनी बहू के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है।

मृतक के पिता का आरोप है कि मई-2011 में संदीप (38) की शादी उत्तर प्रदेश निवासी लड़की से हुई थी। संदीप ने 21 फरवरी को रात करीब 2:17 बजे अपनी बहन पायल को वॉट्सऐप पर मैसेज भेजा था, जिसमें अपनी पत्नी पर परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने शिकायत में बताया कि शादी के बाद से ही उसकी पत्नी की ओर से झगड़ा करना शुरू कर दिया गया। घरवालों से अलग रहने की जिद के चलते रोज-रोज क्लेश करने लगी। जिससे तंग आकर संदीप शादी के दो महीने बाद मुहाना में किराए का मकान लेकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। जिसके बाद उसकी पत्नी आए दिन झगड़ा कर संदीप से रुपए ऐंठने लगी।

- सुसाइड नोट सामने आने के बाद मृतक के पिता ने हत्या का आरोप लगाते हुए बहु के खिलाफ मामला कराया
- आरोप है कि महिला अपने पति और ससुराल पक्ष पर कई झूठे मुकदमें दर्ज करवाकर रुपए ऐंठ चुकी हैं

रिलायंस ने की "डिजिटल डिस्काउंट डेज़" की घोषणा

जयपुर (कासं)। रिलायंस डिजिटल ने अक्षय तृतीया से पहले "डिजिटल डिस्काउंट डेज़ कैंपेन" की घोषणा की है। इसमें ग्राहकों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान ही नहीं, बल्कि फायदेमंद भी होगा। इस कैंपेन के अंतर्गत, ग्राहक लीडिंग बैंक के कार्ड्स पर 26 हजार तक इंस्टेंट डिस्काउंट का फायदा तथा पेपर फाइनेंस पर 30000 तक कैशबैक का विकल्प मिल सकेगा। इसके अलावा, रिलायंस डिजिटल सैकंड प्रोडक्ट पर फ्लैट 50 प्रतिश की छूट देगा, जिससे ऑडियो डिवाइस, वियरेबल्स, मोबाइल और लैपटॉप एक्सेसरीज, चुनिंदा होम एंटरटेनमेंट और छोटे अप्लायंसेज जैसी कैटेगरी में कई चीजें खरीदने को बढ़ावा मिलेगा। इसमें हिस्सा लेने वाले ब्रांड्स में मार्शल, जेबीएल, बोट और वनप्लस शामिल हैं। ब्लूटूथ स्पीकर, नेकबैंड और वायरलेस हेडफोन जैसे प्रोडक्ट्स भी लिस्टेड कीमत से लगभग आधी कीमत पर उपलब्ध होंगे। रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजें जैसे वायरलेस माउस, लैपटॉप एक्सेसरीज, पावर बैंक और सैंडविच मेकर जैसे छोटे किचन अप्लायंसेज भी इस स्कीम का हिस्सा हैं, जो ग्राहकों को 300 से 750 की रेंज में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे।

सहकारिता मंत्री ने किया मसाला मेले का शुभारम्भ

जयपुर (कासं)। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दक ने कहा कि सहकारिता विभाग एवं कॉनफेड द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को एक सशक्त मंच मिलता है तथा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलता है। दक ने शुक्रवार को जवाहर कला केन्द्र में शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा की मौजूदगी में सहकार मसाला मेले का शुभारम्भ किया।

- जवाहर कला केन्द्र में 26 अप्रेल तक चलेगा आयोजन
- 150 स्टॉल्स पर उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण मसाले एवं विविध उत्पाद मिलेंगे

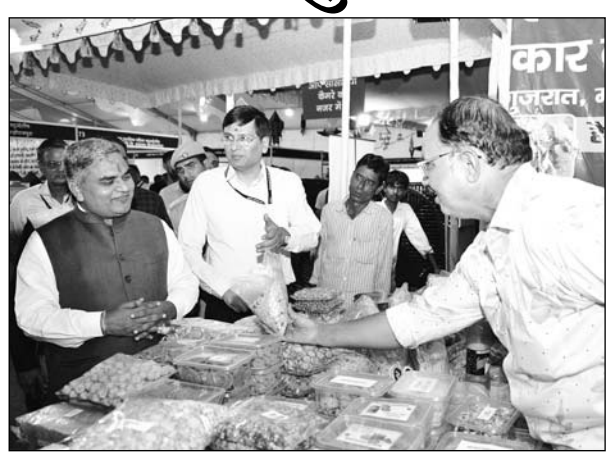

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने जवाहर कला केन्द्र में मसाला मेले का उद्घाटन करने के बाद स्टॉल्स का अवलोकन किया।

सहकारिता मंत्री एवं शासन सचिव ने विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन कर देश और प्रदेश की सहकारी समितियों द्वारा प्रदर्शित मसालों एवं अन्य उत्पादों की जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) द्वारा वर्ष 2003 से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के मसाले एवं अन्य उत्पाद उपलब्ध होते हैं, जिससे यह आयोजन जयपुरवासियों के बीच लोकप्रिय बन गया है। इस वर्ष यह मेला 17 से 26 अप्रेल तक आयोजित किया जा रहा है। मेले में इस बार लगभग 150 स्टॉल्स लगाई गई है। मेले में राजस्थान के साथ-साथ केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि विभिन्न राज्यों की सहकारी संस्थाएं अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय कर रही हैं। साबुत एवं पिसे मसालों के अलावा विशिष्ट क्षेत्रीय उत्पाद भी यहां उपलब्ध हैं।

जनगणना-2027 का पहला चरण 16 मई से

जयपुर (कासं)। जनगणना 2027 के तहत राजस्थान में प्रथम चरण का कार्य 16 मई से शुरू होकर 14 जून तक किया जाएगा। इस चरण में मकानसूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि इस बार जनगणना को पूर्णत: डिजिटल और सहभागी बनाने की दिशा में 'स्व-गणना' की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके तहत नागरिक 1 मई से 15 मई के बीच ऑनलाइन माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। हालांकि, इसके बाद भी प्रगणक द्वारा फील्ड स्तर पर सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। उन्होंने साइबर सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि नागरिक केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें और किसी के साथ साझा न करें।

राज्य में इस कार्य के लिए करीब 1 लाख 60 हजार प्रगणक और पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे, जो घर-घर जाकर डेटा संग्रहण करेंगे। मकान सूचीकरण के दौरान भवनों, परिवारों, उपलब्ध सुविधाओं, परिसंपत्तियों तथा उपभोग से जुड़े कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रथम चरण का उद्देश्य आगामी जनसंख्या गणना के लिए एक सटीक और विश्वसनीय मास्टर फ्रेम तैयार करना है, ताकि दूसरे चरण में कोई भी व्यक्ति या परिवार गणना से वंचित न रह जाए। जनगणना कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्यभर में व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत मास्टर ट्रेनर्स, फील्ड ट्रेनर्स और प्रगणकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

जनगणना प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए पोर्टल, वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं, जिनसे निगरानी और डेटा संग्रहण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी। निदेशक मल्लिक ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना कार्य में सहयोग करते हुए सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं तथा प्रगणक के पहचान पत्र और कोड की जांच के बाद ही जानकारी साझा करें।

- आरोपी की मदद करने वाले दो युवकों को भी पुलिस ने दबोचा

पाइप लाइन गैस कनेक्शन बढ़ाने के निर्देश

जयपुर । जयपुर में अतिरिक्त मुख्य सचिव (खान एवं पेट्रोलियम) अपर्णा अरोरा ने राज्य की सीजीडी (सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन) संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि वे जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाते हुए शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों को डीपीएनजी (डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन से जोड़ें। सचिवालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि सीजीडी संस्थाएं जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को पाइपलाइन से घरेलू गैस सुविधा से जोड़ें और चरणबद्ध तरीके से कॉलोनियों को एलपीजी फ्री जोन घोषित करने की कार्ययोजना तैयार करें। अरोरा ने निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर नियमित मॉनिटरिंग करें और प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। जहां पीएनजी का आधारभूत ढांचा तैयार है, वहां कॉलोनी स्तर पर शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक कनेक्शन जारी किए जाएं।

पीडब्ल्यूसी बैठक में 286 करोड़ रु. के विकास कार्यों को मंजूरी

राजधानी में यातायात व सीवरेज सुधार तथा सौंदर्यीकरण पर जोर दे रहा जे.डी.ए. प्रशासन

जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की पीडब्ल्यूसी (पब्लिक वर्क्स कमेटी) की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को जेडीसी सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शहर के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से सीवरेज, यातायात सुधार और सड़क विकास सहित विभिन्न कार्यों के लिए करीब 286 करोड रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां दी गईं।

बैठक में सचिव गौरव सैनी, निदेशक आयोजना मृणाल जोशी, निदेशक अभियांत्रिकी देवेंद्र गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राजधानी में बढते यातायात दबाव को कम करने के लिए जोन-7 में सिरसी रोड (सी.जोन बाईपास से सिरसी मोड तक) के चौडीकरण एवं विकास कार्य हेतु 48.76 करोड रुपए स्वीकृत किए गए। इसके अलावा सीकर रोड पर चौमूं पुलिया से रोड नंबर 14 तक एट-ग्रेड यू-टर्न निर्माण के लिए 9.54 करोड़ तथा सहकार मार्ग स्थित इमली फाटक और ज्योति नगर टी-जंक्शन सुधार के लिए 5.96 करोड़ रुपए की कार्योत्तर स्वीकृति जारी की गई।

जेडीए कमिश्नर सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को पब्लिक वर्क्स कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई।

शहर में सीवरेज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जोन-5 और 6 से एसटीपी नेवटा तक लेटरल सीवर लाइन बिछाने के लिए 95.16 करोड रुपए स्वीकृत किए गए। वहीं भांकरोटा एवं आसपास क्षेत्रों से एसटीपी नेवटा तक सीवर लाइन के लिए 42 करोड और ग्राम गजधरपुरा स्थित 30 एमएलडी एसटीपी के अपग्रेडेशन हेतु 17.18 करोड रुपए की संशोधित स्वीकृति दी गई।

शहरी सौंदर्यीकरण के तहत विद्याधर नगर के सेंट्रल स्पाइन कॉरिडोर पर सेंट्रल फूड स्ट्रीट के पुनर्विकास एवं रखरखाव के लिए 3.38 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसके अलावा सेक्टर-1 विद्याधर नगर में इंफॉर्मेशन बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट सेंटर निर्माण हेतु 10.50 करोड तथा स्वर्ण जयंती गार्डन की चारदीवारी के लिए 3.02 करोड रुपए मंजूर किए गए।

जोन-11 के अचरावाला, जयसिंहपुरा उर्फ तेजावाला और अभयपुरा में लैंड पूलिंग स्कीम के तहत सड़क एवं अन्य विकास कार्यों के लिए 40.07 करोड़ रुपए की संशोधित स्वीकृति दी गई। इसके अलावा मालवीय नगर में सड़क नवीनीकरण, सी.जोन बाइपास से कनकपुरा फाटक तक सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए 6.85 करोड तथा जाहोता फ्लाईओवर से जाहोता गांव तक सड़क निर्माण के लिए 3.71 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। बैठक में शहर के समग्र विकास, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर व्यापक चर्चा की गई।

एक किलो अफीम के साथ दो गिरफ्तार

जयपुर । राजधानी जयपुर के बगरू थाना क्षेत्र में विशेष नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने बडी कार्रवाई करते हुए एक कार से करीब 1 किलो अफीम बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ठीकरिया टोल प्लाजा पर चल रही सघन नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार को रुकवाकर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन से करीबन 1 किलो अफीम बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी विपुल जाट और राहुल सारण को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी चित्तौड़गढ़ से जयपुर अफीम की सप्लाई के लिए आ रहे थे। पुलिस को आशंका है कि यह नेटवर्क बडे स्तर पर नशे की तस्करी से जुड़ा हो सकता है। यह कार्रवाई बगरू थाना अधिकारी राजेंद्र गोदारा के नेतृत्व में की गई। पुलिस अब आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और तस्करी के पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।